भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2800**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटा

2800. श्री टी. आर. बालू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटा बढ़कर 25 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो वर्ष 2024 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार घाटे में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या संभावित प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार इस अवांछित स्थिति से किस प्रकार निपटने जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटे (पण्यवस्तु और सेवाएँ) में 4.34% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 92.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 88.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इस मामूली वृद्धि के साथ निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2024 में कुल निर्यात 5.32% बढ़कर 607.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2025 में 640.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। समग्र रूप से, वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर 2025) के दौरान भारत का व्यापारिक कार्य-निष्पादन विदेशी व्यापार में लचीलेपन और निरंतर विस्तार को दर्शाता है।

भारत के व्यापार घाटे में मामूली वृद्धि को मजबूत घरेलू मांग और महत्वपूर्ण इनपुट्स, विशेष रूप से ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के निरंतर आयात के प्रतिबिंब के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जो राष्ट्र की विकास गति को रेखांकित करता है । औद्योगिक विस्तार और विकासात्मक प्राथमिकताओं को बनाए रखने के लिए आयात अपरिहार्य हैं, जबकि निर्यात का स्थिर विस्तार एक मजबूत प्रतिसंतुलन प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समग्र घाटा प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर बना रहे।

महत्वपूर्ण रूप से, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण के पर्याप्त स्तर को निरंतर बनाए रखा है, जो सतत आयात संबंधी आवश्यकताओं को सहयोग प्रवाह करने और बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु एक कार्यनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है। यह लचीलापन औद्योगिक आधुनिकीकरण, निर्यात विविधीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए राष्ट्र की व्यापारिक आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने की क्षमता को रेखांकित करता है।

*****